RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी. ओफिस : १३१, धर्मनगर सोसायटी, हाईवे रोड, साबरमती, अहमदाबाद- ३८० ००५. गुजरात, भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 213 | दि. 03-12-2018 सोमवार | वि.सं. 2075 | कारतक वद-11 | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

राज्यभर में खलबली : सरकार ने जांच का आदेश दिया

लोकरक्षक भर्ती दल का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द हुई

पेपर के जवाब के साथ कथित सोशल मीडिया में वायरल होने पर सनसनी करीब एक महीने के बाद परीक्षा फिर से आयोजित करने की संभावना

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

गुजरात पुलिस में लोकरक्षक दल की भर्ती के लिए परीक्षा रविवार को रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने पर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विकास सहाय ने घोषणा करके बताया है कि, पेपर लीक हुआ यह जानकारी मुझे मिली है। जिसकी वजह से यह परीक्षा को रद्द कर दी गई है। पेपर लीक करने वाले लोकरक्षक भर्ती बोर्ड के अधिकारी के साथ रहती एक महिला होने की जानकारी सामने आई है और यह पूरे प्रकरण में मास्टर माइन्ड महिला ने स्वीकार कर लिया है। यह पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द होने पर लाखों उम्मीदवारों ने नाराजगी व्यक्त की, इसके साथ ही राज्यभर में खलबली मच गई। पूरे मामले को गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जांच का आदेश दे दिया है। लोकरक्षक भर्ती दल की नौ हजार बैठकों के लिए रविवार को दोपहर में तीन बजे ली जाने वाली थी, जिसमें अहमदाबाद

सहित राज्यभर में से साढ़े आठ लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। राज्यभर में करीब ढाई हजार केन्द्र पर यह परीक्षा ली जाने वाली थी और उम्मीदवार परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच गये लेकिन उनको कुछ देर पहले ही पेपर के जवाब लीक हो जाने की बात सामने आने पर सनसनी मच गई और आखिर में प्रशासन द्वारा परीक्षा रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। लोकरक्षक भर्ती दल की रद्द की गई परीक्षा अब करीब एक महीने के बाद परीक्षा फिर से आयोजित करने की संभावना है। सरकार द्वारा उम्मीदवार को एसटी का किराया वापस देने की घोषणा की गई थी और आगामी परीक्षा के समय भी एसटी किराया नहीं लेने की घोषणा की गई। लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द होने के कारण रविवार को अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में लाखों उम्मीदवार और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी नहीं दिए जाने से कई सेन्टरों पर उम्मीदवारों को एन्ट्री दे दिया गया था। लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षाखंड से बाहर जाने के लिए कहा गया। जिसे लेकर उम्मीदवारों में भारी नाराजगी फैल गई थी। कई स्थलों पर उम्मीदवारों ने नारेबाजी और मार्ग चक्काजाम किया गया था और विरोध प्रदर्शन किया गया।

अहमदाबाद में शिक्षामंत्री का पुतला दहन

उम्मीदवारों पर पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द हुई इसे लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, पालनपुर, राजकोट, भावनगर, जामनगर, केशोद सहित के कई स्थलों पर नाराज हुए उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन और ट्राफिक-रोड-चक्काजाम, नारेबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थलों पर उम्मीदवारों ने रास्ते में टायरों को जला कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और भाजपा सरकार और रुपाणी हाय हाय के नारे लगाये। जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई, अहमदाबाद में भी गुजरात यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया और शिक्षामंत्री का पुतला दहन किया गया। पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

राज्य में राजकोट सहित के कुछ स्थलों पर भारी नाराजगी व्यक्त कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस द्वारा जमकर लाठीचार्ज किए जाने से पूरे राज्य में कड़ी आलोचना की गई। उम्मीदवारों ने सरकार के विरूद्ध सवाल उठाये थे उनकी की गई मेहनत और मानसिक परेशानी का मुआवजा क्या सरकार के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होने का स्पष्ट किया गया।

लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा का पेपर लीक होने पर रविवार को सरकारी प्रशासन और खुद भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है। सरकार पर विपक्ष सहित के लोगों ने कड़ी आलोचना की। एक तरफ, पेपर लीक मामले में सरकार बेकफूट पर आ गई थी तो दूसरी तरफ लोकरक्षक दल की परीक्षा रद्द होने के बाद गांधीनगर में राज्य के डीजीपी, लोकरक्षक दल के उच्च अधिकारियों, शहर क्राइमब्रांच, साइबर सेल और सरकार के अधिकारियों की बैठकों का दौर और जांच शुरू की गई।

बैठकों में डीजीपी शिवानंद झा, लोकरक्षक दल भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विकास सहाय, क्राइमब्रांच के एडिशनल जोइन्ट सीपी जेके. भट्ट सहित के उच्च अधिकारी और सरकार के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुए।

जगह-जगह विरोध प्रदर्शन : सरकार की आलोचना की गई

सोनाली बेंद्रे काफी समय से कैंसर से लड़ रही हैं

मुंबई में वापस आ रही हैं कैंसर से लड़ रही सोनाली

(संपूर्ण समाचार सेवा)
मुंबई,

ऐक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पिछले काफी समय से कैंसर से लड़ रही हैं। वह अपना इलाज कराने के लिए न्यू यॉर्क में रह रही हैं। हालांकि कैंसर से लड़ाई काफी कठिन होती है लेकिन सोनाली ने जैसे यह लड़ाई लड़ी है वह दूसरों को बहुत प्रेरणादायक है। अब खबर ऐसी आ रही है कि कई महीने न्यू यॉर्क में गुजारने के बाद सोनाली अब मुंबई वापस आ रही हैं सोनाली के एक नजदीकी सूत्रने बताया है कि, सोनाली बेंद्रे ने बहुत बहादुरी से अपना कैंसर का इलाज कराया है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और वह मुंबई वापस आ रही हैं। सोनाली अपने दोस्तों और फैमिली को काफी मिस कर रही हैं। सोनाली ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपनीएक फोटो शेयर की है। फोटो के साथ लिखे कैप्शन को देखकर माना जा रहा है कि वह जल्द ही मुंबई में दिखाई देगी।

जी-२० : आतंकवाद से व्यापार तक

आतंकवाद का मुकाबला करने पर मोदी ने जोर दिया

मोदी ने चर्चा की कि कैसे वैश्विक समस्या बन चुके आतंक के खिलाफ एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा)
ब्यूनस आयर्स,

जी-२० समिट के इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में पीएम मोदी ने संयुक्त रूप से वैश्विक समस्या बन चुके आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया।

मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि यूरोपियन कमिशन के प्रेसिडेंट जीन क्लाउड जंकर, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क और जर्मन चांसलर ऐंगला मर्केल के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे देश संयुक्त रूप से आतंक के खिलाफ एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ के डेटा डेटा संरक्षण नियमों के अनुरूप भारतीय कंपनियों को भी डेटा पर्याप्तता का स्टेटस दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन का नया नियम हाल ही में लागू हुआ है।

यूरोपियन कमिशन के प्रेसिडेंट जीन क्लाउड जंकर और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी ने ट्रेड और फ्री ट्रेड नेगोसिएशन पर भी चर्चा की। गोखले ने बताय, उन्होंने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि भारत इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके संतुलित नतीजे आने चाहिए, जो उद्योग और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंगला मर्केल और नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट के साथ भी सफल बातचीत की। मर्केल के साथ पीएम मोदी ने दुनिया भर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव ने कहा, दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थाएं होने की वजह से दोनों देशों को बहुपक्षीय और यूएन के रोल को और मजबूत करने के लिए साथ काम करना चाहिए।

डच के पीएम के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे दोनों देश साथ मिलकर वॉटर मैनेजमेंट और क्लाइमैट चेंज को स्थायी समाधान देने के लिए तकनीक का सहारा ले सकते हैं। पीएम मोदी ने डच पीएम के साथ भारत में १०० वॉटर-वे बनाने के अपने महत्वकांक्षी प्रॉजेक्ट के बारे में भी चर्चा की।

ओवैसी का राहुल गांधी पर जनेऊधारी अटैक

कांग्रेस पॉकेटमारों की जमात : असुद्दीन ओवैसी

अरे राहुल गांधी तुम क्या जानते हो, हमारी तकलीफ क्या है : तुम तो महलों में जिंदगी गुजारते हो : ओवैसी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
हैदराबाद,

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वह तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, जहां वह सीधे तौर पर कांग्रेस और तेलुगू देशम पार्टी पर हमले कर रहे हैं। मलकपेट के सईदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने जनेऊधारी हिंदू का तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब यहां के युवाओं को जेलों में डाला गया। चंद्रबाबू नायडू की वजह से जिंदगियां बर्बाद हो गईं। क्या ये कांग्रेस के लोग आए। क्या यह जनेऊधारी हिंदू आया जो अपने आपको जनेऊधारी हिंदू कहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पॉकेटमारों की जमात है। ओवैसी ने आगे कहा, अरे राहुल गांधी तुम क्या जानते हो, हमारी तकलीफ क्या है। तुम तो महलों में जिंदगी गुजारे।

क्या तुमने अपने जिस्म पर कभी लाठियां खाईं। क्या तुमको तुम्हारे नाम से मजहब के नाम पर जलील किया गया। क्या तुमसे नाइंसाफी हुई। अरे हमने मुकाबला किया। जम्हूरियत पर यकीन करके किया। हिंदुस्तान के संविधान का इस्तेमाल करके किया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि वह (राहुल) आज टूरिस्ट बनकर यहां आते हैं। एक सभा का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बसों में बिठाकर लोगों को लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि १०० रुपये और एक पैकेट भी दिए गए। ओवैसी ने आगे कहा कि तेलुगू देशम पार्टी और कांग्रेस ये दोनों पॉकेटमारों की जमात है। उन्होंने कहा, तुमको १०० रुपये और कुत्ते का पिशाब मुबारक हो। पियो कुत्ते का पिशाब। तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि ये पार्टियां हमारी कामयाबी को नहीं रोक पाएंगी। ओवैसी ने कहा कि टीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी को यह बात खटकती रहती है कि आखिर यह क्यों शेरवानी पहनकर सबको परेशान कर रहा है।

पाक मीडिया को दिए इंटरव्यू में सिद्धू बोले

पहल हमेशा पाकिस्तान ही करता है : नवजोत सिंह सिद्धू

सिद्धू को आत्ममंथन की जरूरत है : उन्हें समझना चाहिए कि धार्मिक स्थल कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं है : बीजेपी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली,

अपने पाक दौरे के बाद से ही चर्चाओं के केंद्र में रहे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अब पाक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एक पाक न्यूज चैनल ने जब सिद्धू से पूछा कि करतारपुर कॉरिडोर का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं तो इसके जवाब में सिद्धू ने कहा कि पहल हमेशा पाकिस्तान ही करता है। सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सिद्धू को आत्ममंथन की जरूरत है। उन्हें समझना चाहिए कि धार्मिक स्थल कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं है। इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का क्रेडिट जाता है, १२ करोड़ नानक नामलेवा जो अरदास करते थे। पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम को, हिंदुस्तान के वजीर-ए-आजम को क्रेडिट जाता है, लेकिन पहल हमेशा पाकिस्तान ने की है। **(शेष पीछे)**

इस पूरे मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मुझे लगता है कि सिद्धू का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि धार्मिक स्थल कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं है। इस समय उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के शिलान्यास को सिद्धू और पाकिस्तान की तरफ के लोगों ने धार्मिक उद्देश्य से ज्यादा

सिद्धू का विवादित बयान

अंबानी की गोद में बैठे हैं नरेन्द्र मोदी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
कोटा,

इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राजस्थान के कोटा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां भी सिद्धू एक ऐसा बयान दे गए जिस पर विवाद हो सकता है। रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, कांग्रेस ने चार गांधी दिए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बीजेपी ने हमे तीन मोदी दिए। नीरव मोदी, ललित मोदी और एक जो अंबानी की गोद में बैठे हैं, नरेन्द्र मोदी। बता दें कि नवजोत सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में पाकिस्तान जाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सिद्धू द्वारा खुले तौर पर सीएम अमरिंदर सिंह से असहमति जताने के बाद अब पंजाब में उनके साथ कैबिनेट मंत्री ने उनका इस्तीफा मांगा है।

महाराष्ट्र सरकार के सामने कैश संकट

शिरडी ट्रस्ट ने दिया ५०० करोड़ का इंट्रेस्ट फ्री लोन

(संपूर्ण समाचार सेवा)
मुंबई,

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार कैश की कमी से जूझ रही है। ऐसे में उसे एक बड़ा सहारा मिला है। शिरडी के साईबाबा मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को ५०० करोड़ रुपये का इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का फैसला किया है। यह रकम निलवंडे सिंचाई योजना को पूरा करने के लिए दी जाएगी ताकि अहमदनगर जिले की तहसीलों में पीने के पानी की समस्या हल हो सके। आपको बता दें कि चेयरपर्सन बीजेपी नेता सुरेश हवारे हैं, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई योजना के लिए लोन मांगने पर रजामंदी दे दी। खास बात यह है कि इससे पहले किसी सरकारी कॉर्पोरेशन को इतना लोन बिना इंट्रेस्ट नहीं दिया गया है। यहां तक कि लोन की वापसी के लिए समयसीमा भी तय नहीं की गई है। इसी साल फरवरी में सीएम फडणवीस ने एक मीटिंग कर लोन के प्रस्ताव को पारित किया था और रकम जारी करने का निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया। एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि साईबाबा मंदिर ट्रस्ट और गोदावरी-मराठवाड़ा सिंचाई विकास कॉर्पोरेशन ने इसके लिए सहमति पत्र पर साइन किया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के इतिहास में यह स्पेशल केस होगा। अधिकारी ने बताया कि यह प्रॉजेक्ट लंबे समय से अटका है। प्रॉजेक्ट की कुल कीमत करीब १२०० करोड़ है और ट्रस्ट ५०० करोड़ रुपये देगा। जल संसाधन विभाग इस बजट में ३०० करोड़ का प्रावधान कर चुका है और अगले साल ४०० करोड़ देगा। अधिकारी ने बताया कि दो साल में नहर का काम परा होने की उम्मीद हैं।

यह रकम निलवंडे सिंचाई योजना को पूरा करने दी जाएगी ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके

दलित हनुमान पर सीएम योगी ने दी सफाई

सनातन परंपरा को नहीं जानने वाले लोग सवाल खड़े करते हैं

बाल की खाल निकाल रहे हैं लोग : प्रयागराज जिले में आयोजित श्रीकुंभाभिषेकम् महोत्सव में योगी पहुंचे

(संपूर्ण समाचार सेवा)
प्रयागराज,

राम भक्त हनुमान को दलित बताने वाले बयान को लेकर खड़े हो रहे विवाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें धर्म के मर्म की जानकारी नहीं है, वे लोग हर बात संकीर्णता के दायरे में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग संकीर्णता के दायरे में लाकर बाल की खाल निकाल रहे हैं। प्रयागराज जिले में आयोजित श्रीकुंभाभिषेकम् महोत्सव में रविवार को यूपी के सीएम ने कहा कि सनातन परंपरा को नहीं जानने वाले लोग ही सवाल खड़े करते हैं। सीएम योगी ने कहा, किसी के काम पर उंगली उठाना आसान होता है। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो धरती दिव्य लोक में बदल जाए। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब श्रीकुंभाभिषेकम् महोत्सव का आयोजन हुआ है, कांची कामकोटि मठ आदि शंकराचार्य परंपरा का प्राचीन मठ है। उन्होंने कहा, देश और दुनिया में सनातन परंपरा का प्रचार करने में शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती लगे हुए हैं। श्रीकुंभाभिषेकम् महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कुंभ भारत की सनातन परंपरा मानव कल्याण का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं वहीं लोग सवाल खड़े करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, कुंभ महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। देश में चार स्थानों पर कुंभ का पवित्र आयोजन होता है और प्रयाग का कुंभ देश एवं दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। कुंभ दिव्य शक्तियों को अर्जित करने का सुअवसर है। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के हर नागरिक से अतिथियों के स्वागत की अपील भी की।

संपादकिय

मराठों को आरक्षण

(जी.एन.एस.) , महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार इस फैसले के जरिए साबित कर चुकी है कि किसी खास समुदाय को उसके आर्थिक पिछड़ेपन के चलते आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में ठीक यही दलील पार्टी की अन्य राज्य सरकारों को भी सुनने को मिलेगी।महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को स्वीकार करके सरकार ने जनभावना को सम्मान देने की लोकतांत्रिक परंपरा का पालन किया है। राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिस तरह पिछले कुछ समय से प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में इस मांग के इर्द–गिर्द विशाल, लेकिन शांतिपूर्ण यात्राएं और रैलियां आयोजित हुई हैं, उनके बाद इस मांग के पक्ष में मौजूद जन–समर्थन को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता। इसे स्वीकार करने में अनावश्यक देरी लोगों के आक्रोश को विस्फोटक रूप दे सकती थी। आरक्षण सिर्फ गरीबी के आधार पर हो ओर आयकर चुकाने वालो को किसी भी प्रकार का आरक्षण व सब्सिडी नही दी जाना चाहिये! –सुभाष बुड़ावन वाला18,शांतीनाथ कार्नर,खाचरौद, यह भी सही है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यह पहलकदमी लेने से पहले इसे यथासंभव मजबूत तार्किक आधार देने की कोशिश की। राज्य में आबादी का 30 फीसदी से भी ज्यादा होने और राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल किए रहने के बावजूद मराठा समुदाय के ज्यादातर लोग बेहद कठिन आर्थिक स्थितियों में गुजारा करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बताया कि उनकी सरकार ने यह फैसला महाराष्ट्र पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही किया है। बहरहाल, याद रखना जरूरी है कि महाराष्ट्र में 52 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। इस फैसले के लागू होते ही आरक्षण प्रतिशत बढ़कर 68 हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 फीसदी की सीमा से कहीं ज्यादा है। ऐसा अभी तक सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु में ही हो सका है, जहां की 69 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को 1994 में संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र इस तरह का दूसरा अपवाद बन पाता है।

फिलहाल तो इस फैसले के समर्थकों को दुआ करनी होगी कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित इस प्रस्ताव को अदालत में चुनौती न मिले। हालांकि सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और अगर मामला अदालत में जाता भी है तो मजबूती से इसका बचाव किया जाएगा। कुछेक चुनौतियां अन्य स्तरों पर भी आने वाली हैं। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार इस फैसले के जरिए साबित कर चुकी है कि किसी खास समुदाय को उसके आर्थिक पिछड़ेपन के चलते आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में ठीक यही दलील पार्टी की अन्य राज्य सरकारों को भी सुनने को मिलेगी। गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट इसे अपने लिए ब्रह्मास्त्र की तरह लेंगे। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की ओर से ठीक यही तर्क अपने आरक्षण का दर्जा बदलने के लिए दिया जाता रहा है। तात्कालिकता से ऊपर उठ कर देखें तो एक समाज और राष्ट्र के रूप में हमें आरक्षण की निरंतर फैलती मांग का कोई ऐसा हल ढूंढना होगा, जिसमें सभी समुदायों की आकांक्षाओं के लिए पर्याप्त मौके सुनिश्चित हों, लेकिन टैलंट और मेरिट को दोयम दर्जे पर रखकर अंततः एक मीडियॉकर समाज बने रहने की मजबूरी भी राष्ट्र के सामने न आए।

बजट में कहा तो... पर क्या टीबी को हराना आसान है ?

(जी.एन.एस.), आंगन में बैठी इन महिलाओं को गौर से देखिए. इनके माथे पर बिंदी नहीं है. मांग में सिंदूर भी नहीं. ये सभी विधवा हैं. पति को खोने के बाद अब ये लाचार सी जिंदगी जी रही हैं. यह महिलाएं मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक के एक ही गांव जाखनौद के एक मोहल्ले में रहती हैं. इन सभी के पति टीबी के कारण मौत का असमय ही शिकार हो गए. इस जिले में गांव–गांव की ऐसी ही कहानी है, जहां आपको मोहल्ले के मोहल्ले टीबी से पीड़ित मिलेंगे. शिवपुरी ही क्यों, तकरीबन 17 हजार साल पुरानी टीबी की यह बीमारी चुपचाप देश के गांव–गांव में फैल रही है. शिवपुरी जिले के बारे में तो कहा जाता है कि इस जिले में रहने वाले बच्चे कुपोषण से असमय मरते हैं और सहरिया आदिवासी टीबी से.मध्यप्रदेश के ही पन्ना जिले के गांव मनोर को ही ले लीजिए. गांव में सिर का मुंडन करवाए लोग मिले. बच्चों से लेकर बड़े तक. पता चला कुछ दिन पहले ही यहां परिजन की मृत्यु हुई है. कारण टीबी. टीबी से मौत यहां सामान्य बात हो चुकी है. यहां कोई भी व्यक्ति पचास बरस से ज्यादा का नहीं है. यहां सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं पचास साल के लंबू आदिवासी. लंबू खुद टीबी के मरीज हैं. इस गांव में चालीस विधवा महिलाएं रहे चुकी हैं, गांव के लोग आसपास की पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं. आप समझ सकते हैं कि टीबी की गरीबों पर ज्यादा कहर ढाती है. खाली, भूखे पेट पर यह भी उतनी निर्ममता से प्रहार करती है कि इसका शिकार फिर बच नहीं पाता.इस भयंकर बीमारी को 2025 तक जड़ से खत्म करने की घोषणा सरकार ने कर दी है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टीबी और काला–ज्वर को मिटा फेंकने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे हाथों हाथ लिया जाना चाहिए, लेकिन जिस भयंकर रूप में यह हमारे देश में फैली है, क्या उसे देखना लाजिमी नहीं होगा? क्या यह संभव हो पाएगा कि टीबी सचमुच आने वाले नौ–दस सालों में जड़ से खत्म हो जाए, यदि हां तो इसका रोडमैप क्या होगा? अभी तो इसकी गंभीरता को देखते हुए यह लगता है कि यह कम होने की बजाय बढ़ रहा है. जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंक? बताते हैं भारत में साल 2015 में तपेदिक से मरने वालों की संख्या 4,80,000 तक पहुंच गई थी. इंडियन मेडिकल रिसर्च कौंसिल के पर्चों में जब हम इस बीमारी को खोजते हैं तो पाते हैं कि 1900 की शुरुआत में प्रति एक लाख लोगों पर 400 सौ लोग टीबी से प्रभावित थे. 1920 तक चार सौ लोग इससे प्रभावित पाए गए. सन 1950 में हमारे देश में प्रति लाख आबादी पर यह आंकड़ा 200 तक पहुंचा था. इसे आजाद भारत में हम अब तक दो सौ से 111 पर पहुंचा पाए हैं. इसका एक मतलब यह भी मानें कि अंग्रेजों के जमाने में टीबी ज्यादा तेज गति से ठीक हुई. टीबी से संबंधित सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले छह सालों में हमने टीबी से प्रभावित मरीजों को प्रति एक लाख की आबादी पर 17 अंकों तक ही कम किया है. यदि सरकार इसी गति से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कोशिश करती रही तो टीबी पूरी तरह ठीक होने में अब भी तीस साल लगेंगे.आपको बता दें कि यह आंकड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दर्ज होने वाले मरीजों के हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि भारत में टीबी के केवल 58 प्रतिशत मामले ही दर्ज होते हैं. एक तिहाई से ज्यादा मामले या तो दर्ज ही नहीं होते हैं या उनका इलाज नहीं हो पाता है. इसका बड़ा कारण यह है कि गैर सरकारी सेक्टर के अस्पतालों में टीबी को दर्ज किए जाने का अब तक कोई सिस्टम ही नहीं बना है. संगठन का ऐसा अनुमान है कि ऐसे तकरीबन दस लाख और टीबी मरीज देश में हैं जिन्हें पहचाना ही नहीं जा सका है. इसलिए माना यह जाना चाहिए कि टीबी को जितने हल्के में लेकर हम 2025 तक जड़ से मिटा देने की बात कर रहे हैं दरअसल वह इतना आसान है नहीं.देश में सत्तर प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है. गरीबी दूर होने की दर भी वास्तव में कम है. यह समझे जाने की जरूरत है कि टीबी का संबंध व्यापक रूप से पोषण से जाकर जुड़ता है. भूखे पेट रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. इसलिए टीबी भूखे समाज में ज्यादा गंभीरता से सामने आती है. पोषण से भी मतलब केवल सब्जी–रोटी नहीं अपितु संतुलित भोजन से माना जाना चाहिए. इसलिए यहां पर केवल टीबी का इलाज मुहैया करा भर देने से टीबी का खात्मा संभव नहीं है, यह तब मुमकिन होगा जबकि देश में लोगों को रोग प्रतिरोधक ताकत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार भी मिले. इसके लिए लोगों को स्थानीय समाज में मिलने वाले पोषक तत्वों की ओर जाना होगा. टीबी की एक बड़ी बाधा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का कम भरोसा होना भी है. जबकि टीबी के लिए सरकार ने डॉट्स जैसी बेहतरीन सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवा रही है, तब भी लोग इसके इलाज के लिए बड़ीसंख्या में गैर सरकारी संस्थाओं या डॉक्टरों के पास ही जा रहे हैं. जो इलाज शून्य लागत पर हो सकता है, उसके लिए लोग शिवपुरी जिले में हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं. शिवपुरी जिले के ही सोनीपुरा गांव की एक महिला को तो इसके लिए अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी, क्योंकि उसके पति व एक ही साल में तीन–तीन लोग टीबी के चलते मौत का शिकार हो गए.

पहल... (आगे का शेष)

राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है। इससे पहले हैदराबाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, सिद्धू ने कहा था, राहुल गांधी मेरे कैप्टन है। उन्होंने ही मुझे पाकिस्तान भेजा था। राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी कैप्टन हैं। सिद्धू के इस बयान पर पंजाब सरकार के मंत्रियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। मंत्रियों का कहना है कि सिद्धू जिनके पास नगर निकाय और पर्यटन विभाग है अगर वह कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन नहीं मानते हैं तो उन्हें चीफ मिनिस्टर की टीम से इस्तीफा दे देना चाहिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री टी राजिंदर सिंह बाजवा, राजस्व मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सिद्धू को निशाने पर लिया है।

मातृत्व लाभ बनाम मातृत्व हकङ्कएक बेहद अधूरी शुरुआत

(जी.एन.एस.), 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ. इसमें कहा गया कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना शुरू की जा रही है. अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण एवं पौष्टिक आहार के लिए 6 हार रूपये की आर्थिक मदद करेगी. ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जायेगी. देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने में इस योजना से ब ?ी सहायता मिलेगी. वर्तमान में ये योजना 4000 रूपये की आर्थिक मदद के साथ देश के केवल 53 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही थी.(उन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि यह योजना वर्ष 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का हिस्सा है.) इसके बाद 1 फरवरी 2017 को भारत के वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता की राष्ट्रव्यापी स्कीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. इस स्कीम के अंतर्गत उस गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रूपये अंतरित कर दिए जायेंगे, जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देंगी और अपने बच्चे का टीकाकरण करवाएंगी.इसके लिए वास्तविक जरूरत 16.44 हजार करो? रूपये की थी, पर अपने बजट में वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए 2700 करो? रूपये का आवंटन किया है. पिछले वर्ष इसके लिए 634 करो? रूपये के बजट का प्रावधान था. आज देश में लैगिक भेदभाव के खिला? जिस तरह की प्रतिबद्ध नीतियों की जरूरत है, मौजूदा नजरिए और बजट आवंटन दोनों, उसके पक्ष में नजर नहीं आते हैं.प्रधानमंत्री के 31 दिसंबरी संबोधन के बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम का अखिल भारतीय विस्तार किया जा रहा है. अच्छा होगा कि हम शुरुआत में ही अपना दृष्टिकोण सुधार लें और इसे कानूनी मातृत्व हक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करें. हम अनजाने में ही महिलाओं को एक बार फिर ग्राहता हितग्राही के रूप में पेश कर रहे हैं. यह गलत नजरिया है. हम हकों को जैसे ही लाभ के रूप में पेश करते हैं, तभी हकधारिता का अहसास कत्ल हो जाता है.यहीं से सरकारों को कार्यक्रम को लक्षित बनाने का अधिकार भी मिल जाता है. वे शर्तें लगाकर हक धारकों की संख्या को कम करते हैं. यहां भी ऐसी ही शुरुआत हो चुकी है. यदि सचमुच में सभी महिलाओं को यह हक दिया जाए, तो सरकार को एक साल में 16.44 हार करो? रूपये का आवंटन करना चाहिए, परन्तु भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 (तीन माह) और वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के लिए कुल जमा 12661 करोड रूपये खर्च करने की बात कही है.

भारत सरकार इसमें से 7932 करोड रूपये खर्च करेगी. शेष राज्य सरकारों को खर्चना होगा. इसका मतलब है कि सरकार ने वास्तविक जरूरत का 25.67 प्रतिशत आवंटन किया है. यह तय है कि भांति–भांति की शर्तें लगा कर और कम ?र क्रियान्वयन करके लगभग 2.2 करो? महिलाओं को हकों से वंचित किया जाएगा. सरकार ने माना है कि वह 51.70 लाख महिलाओं को इस योजना में लाभ देगी. शेष 74.33 प्रतिशत महिलाओं का क्या होगा? इसका जवाब सरकारों से लेना होगा. इसका असर केवल महिलाओं पर ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों पर बहुत गहरा पडेगा.सरकारी को अपनी बात और जिम्मेदारी पर टिकना चाहिए, पर टिकती नहीं हैं. वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आने के बाद 13 नवंबर 2013 को केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें राज्य का योगदान 25 प्रतिशत और केंद्र का 75 प्रतिशत होगा. फिर 3 फरवरी 2014 को कहा गया कि यह 100 प्रतिशत केंद्र सरकार सहायता की योजना होगी. अब कहा जा रहा है कि इसमें केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य का 40 प्रतिशत होगा. वास्तव में केवल मैदानी क्रियान्वयन ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, बाकी हक का पूरा हिस्सा केंद्र सरकार से आना चाहिए. संकेत दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर शर्तों को पूरा करना राज्य की जिम्मेदारी है. मसलन संस्थागत प्रसव की सम्मानजनक–गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था, सभी बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का जीवन सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य–पोषण और देखरेख की व्यवस्था देना आदि. इनके लिए महिलाओं के हक क्यों सीमित किये जाने चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने इस संबोधन में गर्भवती महिलाओंका ही संदर्भ लिया, जबकि मातृत्व हक के दायरे में धात्री महिलायें, यानी जो महिलायें शिशुओं को स्तनपान करवाती हैं, भी आती हैं. ऐसा लगता है कि राष्ट्र के सबसे ऊंचे स्तर पर अब भी समाज के लैंगिक पहलुओं के बारे में बुनियादी समझ भी स्थापित नहीं हुई है. लैंगिक असमानता के नज़रिये से यह योजना केवल मातृ मृत्यु दर में ही कमी नहीं लाएगी, बल्कि बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और जरूरी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.इन घोषणाओं में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं. मसलन मातृत्व सहायता के साथ ऐसी शर्तों का जो ?ा जाना, जो महिलाओं के हकों और उनकी जीवन के खिला? साबित होंगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के मुताबिक प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान करवाने वाली माताओं को 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है. इसे कानून प्रसूति लाभ कहता है. यह लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जो राज्य या केंद्र या सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित रूप से काम कर रही हैं या जिन्हें किसी दूसरे ?ानून के तहत लाभ मिल रहे हैं. इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानून में किसी अन्य शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था किन्तु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कई ऐसी शर्तें लागू किये जाने के संकेत दिए हैं, जिनसे लगभग 2 करो से ज्यादा महिलाओं को हक नहीं मिल पायेंगे.हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या वे अपने समाज में महिलाओं की स्थिति से वाकिफ हैं? मसलन एक शर्त यह है कि आर्थिक सहायता केवल दो बच्चों के जन्म तक ही दी जायेगी. तीसरे बच्चे के जन्म पर महिलायें इस हक की पात्र नहीं होंगी.

भारतीय समाज में प्रजनन के अधिकार महिलाओं को नहीं मिले हैं. जिस समाज में पुरुष संतान के जन्म की चाहत में स्त्री को बार–बार गर्भवती बनाया जाता है, जहां उसकी इच्छा और निर्णय का कोई मान नहीं होता, वहां यदि तीसरे बच्चे के जन्म पर स्त्री का जीवन अपने आप ही संकट में होता है, वहां सरकार भी उसके जीवन के प्रति असंवेदनशील हो रही है. यह सही है कि दो बच्चों तक परिवार को सीमित रखने का सिद्धांत लागू किया जाना है, किन्तु क्या इसके लिए स्त्री को सजा देना जरूरी है? एक तरफ तो समाज उसकी प्रजनन क्षमता पर अपना शासन चलता है, वहीं मातृत्व हक की योजना में इस तरह की शर्त डालना सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में संविधान के जीवन के बुनियादी अधिकार के खिला? है. भारत में जनगणना–2011 के मुताबिक 29 साल से कम उम्र की 1.6 करो? महिलायें ऐसी हैं, जिन्होंने 3 या इससे ज्यादा बच्चों को जन्म दिया है. उन्हें इस हक से वंचित किया जाएगा. भारत में नीति और योजनाएं बनाने वाले बहुत विद्वान हैं, किन्तु उन्हें खुद पहल करके एक बार अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यह अध्ययन करना चाहिए कि ज्यादातर परिवारों में दो से ज्यादा बच्चे जन्म क्यों लेते हैं? और इसमें महिलाओं के निर्णय की क्या स्थिति होती है?

यह भी संकेत दिया जा रहा है कि जो महिलायें चिकित्सा संस्थान (किसी भी तरह के अस्पताल) में प्रसव करवाएंगी, केवल उन्हें ही मातृत्व हक दिया जाएगा. देश में अब भी हजारों गांव ऐसे हैं, जहां से लोग आसानी से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं. जहां तक सरकार के प्रचार के संदेश पहुंचते होंगे, किन्?तु सेवाएं नहीं पहुंचती. इसके अलावा स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सक नहीं हैं, उनसे पैसा मांगा जाता है, दवाएं नहीं हैं और सबसे वंचित तबकों के साथ खूब जमकर दुर्व्यवहार होते है. जिनके चलते दलित–आदिवासी और गरीब लोग अस्पताल में प्रसव के लिए नहीं पहुंच पाते हैं. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015–16 में भारत में गर्भवती महिलाओं की अनुमानित संख्या 2.96 करो? थी. अध्ययन बताते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों में 22 लाख महिलाओं को मातृत्व हक मिलते हैं, शेष 2.74 करोड महिलायें इससे वंचित रहती हैं. जरा विचार कीजिये कि वर्ष 2015–16 में भारत में 23.56 लाख प्रसव घर पर हुए. इन महिलाओं को भारत सरकार ने हक पाने के लिए अपात्र मान लिया है. भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक बार मानवीय स्वभाव के साथ यह जानना चाहिए कि ये प्रसव घर पर क्यों हुए?

अब तक की योजना में यह शर्त भी रही है कि लाभ केवल 19 वर्ष की उम्र में होने वाले प्रसव पर ही मिलेंगे. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक 5.6 प्रतिशत प्रसव (लगभग 16.57 लाख) 19 साल से कम उम्र में हुए. भारत में विवाह और बाल विवाह की अपनी एक व्यवस्था है, जिसमें परिवार और समाज निर्णय लेता है कि किसका विवाह किस उम्र में और किसके साथ होगा? हमें यह छिपाना नहीं चाहिए कि देश में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं. बाल विवाह के कारण बच्चों के ऊपर गहरे शारीरिक–मानसिक–भावनात्मक असर पडते ही हैं, उस पर उन बच्चियों को मातृत्व हक से वंचित करना संवेदनशील मानवीय नीति नहीं है.

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जिस तरह की योजना बनायी है (3 जनवरी 2017 को प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञप्ति) उससे स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता है कि यदि महिला का गर्भपात हो जाए, तो उसे पूरी राशि मिलेगी या नहीं? इस विज्ञप्ति के अनुसार मातृत्व हक की पहली किश्त गर्भावस्था के पंजीयन पर मिलेगी और दूसरी किस्त संस्थागत प्रसव होने पर और तीसरी किस्त बच्चे जन्म के पंजीयन और 3 महीनों के टीकाकरण के बाद. गर्भपात एक गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात की स्थिति पैदा करता है. सरकार का मकसद पूरी सहायता उपलब्ध करवाकर उस महिला को आघात से उबरने में मदद करना होना चाहिए, न कि उनका बहिष्कार. वर्ष 2015–16 में देश में 9.84 लाख गर्भपात दर्ज हुए थे. इतना ही नहीं मृत शिशु जन्म की स्थिति में भी महिलाओं को पूरे हक का प्रावधान होना चाहिए.भारत में जो महिलायें अपने घर के संचालन–समन्वय और प्रबंधन का काम करती हैं, उन्हें कार्यशील नहीं माना जाता है. जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वे 8 से 15 घंटे श्रम करती हैं. उस श्रम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं चुकाया जाता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में वह योगदान नहीं जुडता है. बेहतर होगा कि सरकार पारंपरिक लैंगिक असंवेदनशीलता से बाहर आए और श्रम को पुनर्परिभाषित करने, पुनर्वितरण और उसके मूल्यांकन की व्यवस्था बनाए. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14.995 करो? महिलायें मुख्य और सीमांत कामगार के रूप में काम करती हैं. इसके साथ ही 5.8 करोड महिलाएं काम की तलाश में हैं. काम की तलाश कर रही ये महिलायें भी कहीं न कहीं काम में जुटी ही रहती हैं. इस मान से 20.795 करोड महिलायें काम से जुडी हुई हैं या काम की जरूरतमंद हैं. लगभग 16 करोड महिलायें आपके घर के प्रबंधन का श्रम करती हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण (2015–16) के मुताबिक भारत में संगठित क्षेत्र में कुल 2.96 करोड लोग ही काम करते हैं. इनमें से महिलाओं की संख्या केवल 60.5 लाख है. संगठित क्षेत्र का मतलब यह है कि जहां एक हद तक श्रम करने वालों के लिए काम के घंटे, अवकाश, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, सामाजिक व्यवहार के लिए समय और सेवानिवृत्ति का सुरक्षित अधिकार निर्धारित है. इस समूह को श्रम कानूनों का संरक्षण मिल पाता है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को ही मातृत्व हक मिल पाते हैं; यानी गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद वेतन के साथ अवकाश, स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव की सेवाएं, जब वे काम पर जाएं, तब कार्यस्थल पर शिशु की देखभाल की व्यवस्था आदि. ये मातृत्व अधिकार दबाव से नहीं अहसास के साथ मिलना चाहिए. संगठित क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी कोई बहुत अच्छी नहीं हैं. वहां भी महिलाओं को मातृत्व हक के मामले में भेदभाव, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न का सामना करना प ?ता है. फिर भी संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए एक व्यवस्था तो है. भारत सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद गर्भधारण के फलस्वरूप होने वाले पारिश्रमिक/मजदूरी के ह्रास की प्रतिपूति करना है. हमें सोचना होगा कि गर्भावस्था और धात्री अवस्था के 15 महीनों की अवधि में कितने पारिश्रमिक का ह्रास होता है और सरकार किस आधार पर मातृत्व हक की राशि तय कर रही है? मौजूदा संदर्भ में यह औसत मह 400 रूपये प्रतिमाह है.

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर

भारत यात्रा के अंतर्गत अहमदाबाद में 5 दिसंबर को आयोजित होगा स्वस्थ भारत मेला

मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल रहेंगे मौजूद

(जी.एन.एस.) , राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर देश भर में भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत यात्रा के तहत लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए अहमदाबाद में 5 दिसंबर को स्वस्थ भारत मेला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री किशोरभाई कानाणी उपस्थित रहेंगे। केन्द्र सरकार के भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम 5 दिसंबर शाम 4.00 बजे कांकरिया तालाब, अहमदाबाद में आयोजित होगा। इस अवसर पर गुजरात की लोकप्रिय कलाकार किंजलबेन दवे की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इट राइट इंडिया अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उचित खानपान को लेकर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरे देश में स्वस्थ भारत यात्रा निकाली जा रही है। गोवा से शुरू होकर दमन होते हुए इस यात्रा ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध गुजरात के दांडी में प्रवेश किया। यहां से नवसारी, सूरत, भरुच, वडोदरा, गोधरा, संतरामपुर, बालासिनोर, और नड़ियाद समेत नौ जिलों का भ्रमण करते हुए यात्रा आज अहमदाबाद पहुंची । यात्रा के कार्यक्रम के तहत कांकरिया में स्वस्थ भारत मेले का आयोजन किया गया है। यहां से यात्रा राजधानी गांधीनगर, मेहसाणा और 12 दिसंबर को बनासकांठा जिले के पालनपुर से होते हुए राजस्थान के लिए आगे बढ़ेगी। गुजरात में 24 दिनों के प्रवास के दौरान यात्रा राज्य के 12 जिलों में घूमते हुए 791 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा के दौरान सभी जगहों पर नागरिकों को पोषक तत्वों वाले गुणवत्ता युक्त भोजन के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार गुजरात में सभी नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और फोर्टिफाइड फुड मिले तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिशन) की कमी और कुपोषण को दूर करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से योग्य मार्गदर्शन का आयोजन शुरू किया है। इसके अलावा, विवाह एवं सार्वजनिक समारोहों तथा होटल आदि जगहों पर भोजन की बर्बादी को रोकने एवं समाज के गरीब वर्ग तक यह भोजन योग्य चैनल के जरिए पहुंचे इसके लिए एनजीओ की मदद से जागरुक किया जाएगा।

औषधीय ज्ञान की परंपरा बरक़रार

(जी.एन.एस.) प्रदेश में जहां कई जनजातियां विकास की ओर अग्रसर हैं, वहीं कुछ जनजाति आज भी अपने परम्परागत रीति–रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के साथ विकास की दौड़ में काफी पीछे हैं। वे आज भी हर तरह के बीमारी के लिए जड़ी–बूटियों पर निर्भर हैं और उसी से अपना इलाज करते हैं। ये आदिवासी वनों के साथ आंख खोलते और वनों के साथ सोते हैं। ये लोग जंगलों में निवास करने तथा वनोपज पर आश्रित होने के कारण जंगली जड़ी–बूटियों, झाड़–फूंक और टोने–टोटके के अच्छे जानकार होते हैं। इन जनजातियों का प्रकृति के साथ अद्भुत सामन्जस्य होता है। यही कारण है कि इनकी अपनी परम्परागत चिकित्सा पद्धति रही है। लेकिन वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा बदलावा आया है। विकास के नाम पर बाहरी समाज के लोग उनकी परंपरा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनजातीय समाज के शहरों के सम्पर्क में आने से खासकर उनके चिकित्सा पद्धति में बदलाव आया है। जंगलों की अवैध कटाई और जंगलों में आदिवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध ने भी उनकी स्वास्थ्य नीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। अब वे जड़ी–बूटियों के साथ–साथ गंभीर बीमारी के लिए शहर के चिकित्सकों के पास जाने लगे हैं। आदिवासियों के परंपरागत ज्ञान पर काम करने वाले डा. विजय चौरसिया मानते हैं कि अभी इसका प्रतिशत केवल 15–20 है, लेकिन जल्द इनके परंपरागत ज्ञान को नहीं सहेजा गया तो यह विलुप्त भी हो सकता है।

जनजातीय समुदायों का वह पारम्परिक ज्ञान बहुत समय तक लिपिबद्ध नहीं हो सकी। आज भी प्रायः उनका वह पारम्परिक ज्ञान अलिखित ही है। इस परम्परागत ज्ञान में जहां मौखिक साहित्य विशेष हैं, वहीं विभिन्न कौशलों से संबंधित अनुभव भी सम्मिलित हैं। पारम्परिक ज्ञान में कृषि, हस्त–शिल्प, नृत्य–संगीत, चित्रकला, आखेट, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और वनस्पतियों की पहचान और उनके औषधीय उपयोग से संबंधित ज्ञान प्रमुख हैं। जनजातीय समुदायों में परम्परागत रूप से प्रचलित यह ज्ञान आज भी समाज को लाभान्वित कर रहा है। फिर जनजातियों के परम्परागत ज्ञान को खत्म क्यों कर रहे हैं? उस ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने पर गंभीरता पूर्वक विचार और प्रयास किए जाने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार 43 जनजातियों/जनजाति समूह हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.27 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। इनमें से बैगा, भारिया और सहरिया को आदिमजाति समूह का दर्जा प्राप्त है। अर्थात ये तीनों जनजातियां विकास की दृष्टि से अन्य जनजातियों की तुलना में न केवल अधिक पिछड़ी है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक स्तर और भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी पिछड़ी हैं। इसके बावजूद इन तीनों जनजातियों का पारंपरिक ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। मण्डला–डिण्डौरी आदि क्षेत्रों के बैगा, पातालकोट (छिन्दवाड़ा) के भारिया और शिवपुरी, गुना, श्योपुर कलां आदि जिलों के सहरिया परम्परागत औषधीय ज्ञान के आधार पर अनेक रोगों का उपचार करते हैं। बैगा झाड़–फूंक के साथ–साथ पारम्परिक पद्धति से उपचार के लिए प्रसिद्ध है। सहरिया और भारिया क्षेत्रों में भी अनेक पारम्परिक चिकित्सक अपने–अपने समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। चिकित्सा की यह पद्धति आदिवासी लोक–चिकित्सक को परम्परागत रुप से पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होती आ रही है। वन संपदा और वन प्रणीयों आदि के संबंध में ये दक्ष होते हैं। बात डिंडौरी जिले के बैगा जनजाति की करें या बैतूल के गोंड जनजाति की। ये झाड़–फूंक और टोने–टोटके के अच्छे जानकार होते हैं। हमारे जनजीवन में वनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वन जहां एक ओर वनवासियों के लिये अजीविका के स्त्रोत उपलब्ध कराते हैं, वहीं उनकी जीवन रक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जंगलों से आदिवासियों को न केवल वनोपज प्राप्त होता है, बल्कि औषधियों का अक्षय भंडार भी उन्हें वहीं से मिलता है। आदिवासी बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के बजाय सिरहा, गुनिया, देवार, भुमका, ओझा अथवा इसी प्रकार के अन्य अपने परंपरागत चिकित्सकों के पास जाते हैं। ये वनवासी लोक चिकित्सक बीमार की दशा और बीमारी के लक्षणों के आधार पर उसकी चिकित्सा के लिये परंपरागत झाड़–फूंक, तंत्र–मंत्र, पूजा–अनुष्ठान अथवा जड़ी–बूटियों का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा की ये पद्धतियां आदिवासी के लोक चिकित्सक को परंपरागत रुप में पूर्वजों से प्राप्त होती है। इस चिकित्सा ज्ञान का हस्तांतरण पीढ़ी–दर–पीढ़ी आदिवासियों में होता आ रहा है। वैसे इसमें भी थोड़ा बदलाव आया है। अब पुराने पीढ़ी के आदिवासी नई पीढ़ी को अपना ज्ञान नहीं देते हैं। इसके पीछे की धारणा को बताते हुए बैगा जनजाति के वैद्य टिकुआ बैरागी कहते हैं कि धार्मिक मान्यता के कारण पुरानी पीढ़ी द्वारा पारंपरिक औषधीय ज्ञान नई पीढ़ी को नहीं दिया जा रहा है। मान्यता के मुताबिक किसी औषधि के बारे में अन्य को बताने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके पीछे औषधीय पौधे के प्रति धार्मिक आस्था, पूजा और नियम के बंधन भी जुडें हैं। इसलिए आदिवासियों को इससे अनष्टि होने का डर रहता है। दूसरी ओर नई पीढ़ी भी इस ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहती है, क्योंकि यह रोजगारपरक नहीं है और युवाओं को रोजगार चाहिए। देखा जाए तो झाड़–फूंक, तंत्र–मंत्र, पूजा–अनुष्ठान तो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। इससे कभी–कभी सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, लेकिन इस प्रकार की चिकित्सा का कोई वैज्ञानिक आधार अथवा तर्क प्रायः नहीं होता है।

परम्परागत औषधीय ज्ञान और जनजातीय स्वास्थ्य

(जी.एन.एस.), भारत के जातीय इतिहास पर नजर डालें तो यहां की जनजातीयों में आदिम परम्परा के सूत्र दिखाई देते हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक जनजातियां अपनी परम्परा जीवनषैली और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ आबाद हैं। इन जनजातियों के रहन–सहन, खान–पान और परम्पराओं में उनकी भौगोलिक स्थितियों और सामाजिक संरचना के अनुरूप अंतर देखा जा सकता है। विभिन्न जनजातियों की अलग–अलग बोली–भाषा है, जिनमें उनका परम्पारिक ज्ञान सुरक्षित है। आदिम युग से संचित उनका यह ज्ञान जीवन के विभिन्न अनुभवों को समेटे हुए है, जो प्रायः पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जनजातीय समुदायों का वह पारम्परिक ज्ञान बहुत समय तक लिपिबद्ध नहीं हो सकी। आज भी प्रायः उनका वह पारम्परिक ज्ञान अलिखित ही है। इस परम्परागत ज्ञान में जहां मौखिक साहित्य विशेष हैं, वहीं विभिन्न कौशलों से संबंधित अनुभव भी सम्मिलित हैं। पारम्परिक ज्ञान में कृषि, हस्त–शिल्प, नृत्य–संगीत, चित्रकला, आखेट, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और वनस्पतियों की पहचान और उनके औषधीय उपयोग से संबंधित ज्ञान प्रमुख हैं। जनजातीय समुदायों में परम्परागत रूप से प्रचलित यह ज्ञान आज भी समाज को लाभान्वित कर रहा है। सवाल यह उठता है कि इतने अनुभव और ज्ञान के बावजूद आज जनजातीय समुदायों में उसके अनुपात में विकास और समृद्धि क्यों नहीं है। कहीं यह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जनजातियों का परम्परागत ज्ञान लुप्त होना तो नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह चिंता का विषय है और उस ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने पर गंभीरता पूर्वक विचार और प्रयास किए जाने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार 43 जनजातियों/जनजाति समूह हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.27 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। इनमें से बैगा, भारिया और सहरिया को आदिमजाति समूह का दर्जा प्राप्त है। अर्थात ये तीनों जनजातियां विकास की दृष्टि से अन्य जनजातियों की तुलना में न केवल अधिक पिछड़ी है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक स्तर और भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी पिछड़ी हैं। इसके बावजूद इन तीनों जनजातियों का पारंपरिक ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। मण्डला–डिण्डौरी आदि क्षेत्रों के बैगा, पातालकोट (छिन्दवाड़ा) के भारिया और शिवपुरी, गुना, श्योपुरकलां आदि जिलों के सहरिया परम्परागत औषधीय ज्ञान के आधार पर अनेक रोगों का उपचार करते हैं। बैगा झाड़–फूंक के साथ–साथ पारम्परिक पद्धति से उपचार के लिए प्रसिद्ध है। सहरिया और भारिया क्षेत्रों में भी अनेक पारम्परिक चिकित्सक अपने–अपने समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत ज्ञान के आधार पर रक्तचाप और हृदय रोग के लिए अर्जुन की छाल, किडनी रोग के लिए अश?वगंध और अजवाइन, कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए लहसुन, तुलसी आदि, पथरी के लिए आपामाला बेल, भुंई आंवला और चरचटा की जड़ें, टीबी के लिए अड़ूसा और बहेड़ा की छाल आदि, पीलिया के लिए काली हारकंद, आम की छाल, कनेर की बेल और भुंईयां आंवला की जड़ के साथ मिश्री आदि का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। जनजातीय गोदना भी अलंकार के साथ–साथ लोकप्रिय उपचार पद्धति है। विभिन्न जनजाति समूहों में शरीर के विभिन्न अंगों पर अनेक प्रकार की चित्राकृतियां गुदवाने की परंपरा है। यह कार्य विशेष रूप से ओझा, बादी, देवार आदि जाति–जनजाति की महिलाएं करती हैं। जनजातियों में लड़कियों को प्रायः आठ वर्ष की उम्र में पहला गोदना गुदवाया जाता है। विवाह के बाद भी कुछ गोदने अनिवार्य रूप से उन्हें गुदवाने पड़ते हैं। यह सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य परम्परा है। बैगा जनजाति की स्त्रियां पूरे शरीर में गोदने गुदवाती हैं। उनकी मान्यता के अनुसार गोदना एक ऐसा आभूषण है, जो मृत्यु के बाद भी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। उपचारों के रूप में भी गोदना का उतना ही महत्व है। डिण्डौरी जिले के गोदना उपचारक चमरसिंह मरावी बताते हैं कि गठियां–बात और घेंघा जैसे रोग गोदना उपचार से ठीक हो जाते हैं। सिरदर्द का भी यह मुफीद इलाज है। वे कहते हैं कि औषधियों का प्रभाव भीतर तक होने से रोग ठीक हो जाता है। पातालकोट क्षेत्र के प्रताप सिंह भारती जड़ी–बूटियों के विशेष जानकार हैं। उनका कहना है कि जंगल में पौधों को पहचानना एक कठिन काम है। पौधे विषैले भी होते हैं, जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बिना जानकारी के औषधि के रूप में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञान पुरखों के अनुभव से मिला है। इन वन औषधियों का ज्ञान अब जनजातियों की नई पीढ़ी को कम ही है। जनजाति समुदायों को परम्परागत ज्ञान और अनुभव के आधार रोगों का कारण ज्ञात है, इसलिए इनका उपचार भी वे परम्परागत ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते हैं। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और आधुनिक सहायता के सम्पर्क में आने और पारम्परिक ज्ञान के प्रति आस्था और रूचि न होने के कारण जनजाति समुदायों का परम्परागत ज्ञान पुरानी पीढ़ी के साथ ही समाप्त होता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण पुरानी पीढ़ी द्वारा पारम्परिक औषधीय ज्ञान नई पीढ़ी को समय रहते ना देना भी है। इसी कारण से धीरे–धीरे औषधीय पौधों की पहचान और उसके उपयोग की जानकारी समाप्त होती गई है। यदि पारम्परिक ज्ञान पद्धतियों को समय रहते प्रोत्साहित किया जाए तो बहुत सारा ज्ञान हम आज भी बचा सकते हैं। जो आधुनिक पद्धतियों के विकास के लिए आधार बन सकता है। अब भी समय है, जनजातीय समुदायों के पास उपलबध कृषि, सिंचाई, हस्तकलाएं, नृत्य–संगीत, आखेट, वनस्पति और औषधियों आदि के ज्ञान को विभिन्न माध्यमों से संरक्षित करते हुए उसे लोकप्रिय बनाने की योजनाओं पर कार्य करें।

सेटेलाइट आवास क्षेत्र में स्थित एएमसी के तालाब में हाल में कचरा डाला जा रहा है जो बीमारी को निमंत्रण देता है। (संपूर्ण समाचार सेवा)

कांग्रेस के अवसर नाकिया ने जसदान उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया

अहमदाबाद, तीन दिसम्बर (भाषा) कांग्रेस उम्मीदवार अवसर नाकिया ने गुजरात के जसदान विधानसभा सीट पर 20 दिसम्बर को होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल किया।निवर्तमान विधायक कुंवरजी बावलिया के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चले जाने और दो जुलाई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव आवश्यक हो गया था।कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को उपचुनाव के लिए नाकिया के नाम की घोषणा की थी। चुनाव अधिकारी को सोमवार को नामांकन फॉर्म सौंपने से पहले नाकिया ने जसदान में अपने समर्थकों की रैली निकाली जिसमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो–अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है।

अहमदाबाद, तीन दिसम्बर (भाषा) कांग्रेस उम्मीदवार अवसर नाकिया ने गुजरात के जसदान विधानसभा सीट पर 20 दिसम्बर को होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल किया। निवर्तमान विधायक कुंवरजी बावलिया के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चले जाने और दो जुलाई को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव आवश्यक हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को उपचुनाव के लिए नाकिया के नाम की घोषणा की थी। चुनाव अधिकारी को सोमवार को नामांकन फॉर्म सौंपने से पहले नाकिया ने जसदान में अपने समर्थकों की रैली निकाली जिसमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा और विपक्ष के नेता परेश धनानी भी मौजूद थे।

भोपाल गैस घटना : मानव इतिहास की भयंकर त्रासदी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

भोपाल में मानव इतिहास की एक सबसे भयंकर औद्योगिक रिसाव की घटना हुई। जहरीली गैस के इस खौफनाक रिसाव में हजारो जानें चली गई। इस तबाही का अंत यही नहीं हुआ बल्कि आज तक इसका विनाशक असल पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी की इस घटना का नाम सुनते ही आज भी लोग सहम जाते हैं। आइए इस दुखद घटना से जुड़ी सारी बाते इस प्रकार हैं।

- ♦ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने १९६९ में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खली थी। इसके १० सालों बाद १९७९ में भोपाल में एक प्रॉडक्शन प्लांट लगाया।
- ♦ इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेविन था। सेविन असल में कारबेरिल नाम के केमिकल का ब्रैंड नाम था।
- ♦ इस घटना के लिए यूसीआईएल द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कारबेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल कर थी जबकि यूसीआईएल ने मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) का इस्तेमाल किया। एमआईसी एक जहरीली गैस थी। चूंकि एमआईसी के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफी कम पड़ता था, इसलिए यूसीआईएल ने एमआईसी को अपनाया।
- ♦ भोपाल गैस दुर्घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। १९८१ फॉसजीन गैस रिसाव हो गया था जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी।
- ♦ जनवरी १९८२ में एक बार फिर फॉसजीन गैस का रिसाव हुआ जिसमें २४ वर्कर्स की हालत खराब हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- ♦ फरवरी १९८२ में एक बार फिर रिसाव हुआ। लेकिन इस बार एमआईसी का रिसाव हुआ था। उस घटना में १८ वर्कर्स प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स का क्या हुआ अब तक पता नहीं चल पाया।
- ♦ अगस्त १९८२ में एक केमिकल इंजिनियर लिक्विड एमआईसी के संपर्क में आने के कारण ३० फीसदी जल गया। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर एमआईसी का रिसाव हुआ। उस रिसाव को रोकने के लिए एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया।
- ♦ उसके बाद साल १९८३ और १९८४ के दौरान कई बार फॉसजीन, क्लोरीन, मोनोपेथलमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एमआईसी का रिसाव हुआ।
- ♦ इन रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल १९८० के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी ने सिस्टम के रखरखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने एमआईसी का उत्पादन भी नहीं रोका और अप्रयुक्त एमआईसी का ढेर लगता गया।
- ♦ राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने १९८२ से १९८४ के बीच इस पर चार आर्किकल लिखे। हर आर्टिकल में यूसीआईएल प्लांट के खतरे से चेताया।
- ♦ नवंबर १९८४ में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था जिसमें एमआईसी ४२ टन थे जबकि सुरक्षा की द्रष्टी से एमआईसी का भंडार ४० टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था।
- ♦ २–३ दिसंबर, १९८४ की खौफनाक रात। एक साइट पाइ से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया।
- ♦ स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आइरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर २०० डिग्री सेल्सियस हो गया जबकि तापमान ४ से ५ डिग्री के बीच रहना चाहिए। इसमें टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इसमें टैंक पर इमर्जेंसी प्रेशर पड़ा और ४५–६० मिनिट के अंदर ४० मीट्रिक टन एमआईसी का रिसाव हो गया।
- ♦ टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनोमेथलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन सायनाइड और फॉसजीन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोलाल का पूरा पूर्वी इलाका आ गया।
- ♦ गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोंगो को घुटन, आंखों में जनल, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर २००० के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाके के पेड बंजर हो गए। अस्पतालों में भीड़ लग गई। एक समय में १७००० लोगों को अस्पतालो में भर्ती कराया गया।
- ♦ सरकारी आंकड़े के मुताबिक तुरंत २२५९ लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या ३७८७ बताई थी। इस घटना का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालक वॉरन एंडरसन को बनाया गया था। २० सितंबर, २०१४ को उसकी मौत हो गई। घटना के बाद तुरंत भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया था।

प्रतिदिन करीब 30 हजार लोग आ रहे हैं स्टैच्यू आफ यूनिटी देखने- गुजरात के अधिकारी

(जी.एन.एस.) वडोदरा, तीन दिसम्बर (भाषा) गुजराज के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' अब देश के शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक बनती जा रही है और उसे देखने के लिए प्रतिदिन करीब 30 हजार लोग पहुंच रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। गुजरात के मुख्य सचिव जे एन सिंह और राज्य के प्रधान सचिव (पर्यटन) एस जे हैदर दोनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वहां प्रतिदिन 30 हजार पर्यटक आ रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची यह मूर्ति केवडिया में सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को किया था।अमेरिका के महा–वाणिज्यदूत एडगार्ड कागन सोमवार को स्मारक देखने पहुंचे।कागन ने अपने दौरे के बाद कहा, ''यह मूर्ति बहुत प्रभावशाली है और मुझे इसके निर्माण का उद्देश्य जान कर बहुत खुशी हुई।''

अगर राम मंदिर नहीं बना तो लोगों का बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा - रामदेव

(जी.एन.एस.)

रामदेव ने कहा, राम राजनीति का विषय नहीं हैं बल्कि देश का गौरव हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति, गौरव और हमारी आत्मा हैं। उन्हें राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने राम मंदिर निर्माण के लिए फिर अध्यादेश लाने की मांग की रामदेव बोले– मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा बीजेपी से उठ जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर के लिए एक अध्यादेश ला सकती है- बाबा रामदेव राम हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा हैं, राजनीति से ना जोड़ें- रामदेव योग गुरु रामदेव ने रविवार को अहमदाबाद में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग करते हुए कहा कि अगर अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो लोगों का बीजेपी पर से भरोसा उठ जाएगा।

रामदेव ने कहा, एक लोकतंत्र में संसद न्याय के लिए शीर्ष मंदिर है और नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए एक अध्यादेश ला सकती है।योग गुरु ने कहा, अगर मंदिर नहीं बना, वह भी तब जब करोड़ों लोग उसे बनते

हुए देखना चाहते हैं तो लोगों का बीजेपी पर से भरोसा उठ जाएगा जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। रामदेव की यह टिप्पणी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में तेजी लाने की मांग के बीच आई है। रामदेव ने कहा, राम राजनीति का विषय नहीं हैं बल्कि देश का गौरव हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति, गौरव और हमारी आत्मा हैं। उन्हें राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को खुद से मंदिर बनाना है तो इसका मतलब होगा कि वे या तो न्यायपालिका या संसद का सम्मान नहीं करते। पिछले सप्ताह, देश के विभिन्न हिस्सों से राम भक्त मंदिर के निर्माण पर जोर देने के लिए एक दक्षिणपंथी समूह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जनसभा में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे।

गुजरात में ब्राह्मण–राजपूत, तो महाराष्ट्र में ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए मांगा आरक्षण

(जी.एन.एस.)

महाराष्ट्र सरकार के मराठों को 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद से गुजरात के राजपूत–ब्राह्मण और महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण की मांग की है। महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पाटीदारों के बाद अब राजपूतों और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने भी आरक्षण की मांग की है। गुजरात में अतिरिक्त आरक्षण कोटे के लिए समुदाय के लोगों ने ओबीसी आयोग को पत्र भी लिखा है। वहीं, ढ्ढरूढ्ढरू प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है। इस बाबत उन्होंने एक विडियो ट्वीट कर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल में गुरुवार को मराठों को शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हो गया। गुजरात में राजपूत समुदाय के नेताओं ने कहा है कि वे कुल

जनसंख्या का महज 8 फीसदी हैं और महाराष्ट्र में मराठों की तरह वह राज्य में 8 फीसदी रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उधर, समस्त गुजरात ब्रह्म समाज ने ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर उन्हें ओबीसी में शामिल करने के लिए सर्वे की मांग की है। गुजरात ब्रह्म समाज के मुखिया यग्नेश देव ने कहा कि गुजरात में ब्राह्मणों की संख्या 60 लाख है जो कुल जनसंख्या का 9.5 फीसदी है। उन्होंने कहा कि 42 लाख ब्राह्मण आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

चावला ने स्वीकारी हाफिज सईद से करीबी रिश्ते की बात, कहा– हां मैं हूं आतंकवादी

(जी.एन.एस.)

पाकिस्तान के खलिस्तान समर्थक गोपाल चावला की हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तस्वीरें सामने आईं, जिनसे काफी विवाद हुआ। इस पर जब चावला से पूछा गया, तो जानिए उसने क्या कहा-पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के साथ पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन चावला का कहना है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत मेरे बारे में क्या सोचता है। एनबीटी ने जब चावला से संपर्क साधा तो उसने साफ कहा, %भारत मुझे आतंकी मानता है तो हां, मैं हूं आतंकी।% चावला ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ करीबी होने की बात भी कबूल की। चावला से जब पूछा गया कि एक तरफ वह पंथ की बात करता है और दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाता है, तो उसका कहना था कि हाफिज सईद उसकी और पाकिस्तान वालों की नजर में मसीहा है। चावला ने यह मानने से इनकार किया कि ब्रिटेन के कुछ चरमपंथी सिख संगठनों ने पाकिस्तान में ऑफिस खोले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भारत आए वापस, कहा– गोपाल चावला को नहीं जानता सिद्धू के साथ फोटो क्यों खिंचवाई, इस पर चावला ने कहा, वह (नवजोत सिंह सिद्धू) करतारपुर कॉरिडोर के समारोह में आए तो मैंने उनके साथ फोटो ले ली।% पाकिस्तान में ही सिखों के साथ हो रही बदसलूकी पर पूछे गए सवालों पर उसके पास जवाब नहीं थे। कुछ महीने पहले पाक के पहले सिख पुलिसवाले को घर से निकाल दिए जाने जैसे मसले पर उसका कहना था कि उस पुलिसवाले को हीरो बना दिया गया। राहुल गांधी मेरे कप्तान, उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेजा- नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के ननकाना साहिब में अभी तक गुरुनानक देवजी के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, जबकि सिख दो बार आवाज उठा चुके हैं, यह पूछे जाने पर चावला इमरान खान का गुणगान करने लगा।

अहमदाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर हुये संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत, पांच घायल

(जी.एन.एस.),अहमदाबाद,

अहमदाबाद के दुधेश्वर इलाके में शनिवार देर रात संपत्ति विवाद को लेकर दो समूहों के बीच हुये एक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। माधवपुर के पुलिस निरीक्षक वी एन रबाड़ी ने रविवार को बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर कुछ लोगों के एक समूह ने मोहम्मद इरफान सैयद (30) पर तलवार से हमला किया और गोली मार दी। घायल होने के कारण नजदीक के एक अस्पताल में सैयद ने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि संघर्ष में पांच अन्य लोग घायल भी हो गये और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि अशफाक सैयद ने देर रात 11 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी के मुताबिक संपत्ति के एक पुराने विवाद के कारण उस पर और अन्य लोगों पर लोगों के एक समूह ने तलवारों और लोहे की छड़ों से हमला किया।

सैयद ने अपनी शिकायत में हमले के लिए स्थानीय निवासी सुलेमान पठान और दस अन्य का नाम लिया है। इसके बाद शस्त्र कानून के साथ–साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 327 (खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाना), 145 (गैर कानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत एक मामला दर्ज किया गया। रबाड़ी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

सीबीआई–सीबीआई- चीफ जस्टिस बोले–आज पूरी बात सुनूंगा

(जी.एन.एस.)

सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने दलीलें दीं। वहीं एके बस्सी के वकील ने चीफ जस्टिस से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। सीबीआई बनाम सीबीआई मालमे की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बोले आज सबकी बात सुनूंगा, रहें शांत आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन ने कहा कि उनके मुवक्किल के मामले में नियमों का पालन नहीं

दो बजे तक सुनवाई स्थगित करने के बाद इस मामले की फिर शुरू हुई सुनवाई। सीबीआई के भीतर मचे अंदरूनी घमासान पर पिछली बार सुनवाई को अचानक स्थगित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस के. एम. जोसेफ ने आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन से पूछा कि मान लीजिए, अगर सीबीआई डायरेक्टर ही रंगे हाथ अपराध करते पकड़े गए तो क्या उनका तबादला किया जा सकता है? इस पर नरीमन ने कहा कि तब सरकार को सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाले पीएम के तीन सदस्यीय पैनल से इजाजत लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई ने नरीमन से कहा कि अदालत पहले इस पर विचार करेगी कि क्या आलोक वर्मा से उनके अधिकार छीने जाने के लिए पीएम के पैनल की मंजूरी अनिवार्य है या नहीं। अदालत में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हो रही है। वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से दलीलें दीं। दोपहर एक बजे के बाद सीजेआई ने सुनवाई को 2 बजे तक के लिए टाल दिया। सुनवाई जब दोबारा शुरू हुई तब सीजेआई ने आलोक वर्मा की याचिका पर टिप्पणी की, हम आरोप–प्रत्यारोपों में नहीं जा रहे। हम इस मुद्दे की जांच विशुद्ध रूप से कानून के विषय के रूप में कर रहे हैं। नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए वर्मा के जवाब लीक होने पर दलील दी कि मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते हैं। बता दें कि 20 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा का सीलबंद जवाब मीडिया में लीक होने पर नाराजगी जताई थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी कि आप सब सुनवाई के काबिल नहीं हैं। तब नरीमन ने सीलबंद जवाब लीक होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और कहा था कि रिपोर्ट कैसे लीक हुई, उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ अंडमान ट्रांसफर किए गए अधिकारी ए. के. बस्सी के वकील राजीव धवन ने आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से कहा कि पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि हम सब सुनवाई के काबिल नहीं हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। तब चीफ जस्टिस ने धवन से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, परंतु हम आज आपको पूरा सुनेंगे। कृपया आप शांत रहें। इसपर धवन ने कहा कि वह शांत हैं। दोपहर दो बजे तक मामले की सुनवाई टालने के बाद शीर्ष अदालत ने फिर इसकी सुनवाई शुरू की। नरीमन ने शीर्ष अदालत में अपने जिरह में कहा कि पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमिटी ही सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है और निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम दो साल होता है। अगर इस दौरान असाधारण स्थितियां बनती हैं और सीबीआई निदेशक का ट्रांसफर किया जाना है तो कमिटी की अनुमति लेने का प्रावधान है। नरीमन ने कहा कि उनके मुवक्किल के मामले में ट्रांसफर में नियमों का पालन नहीं किया गया। नरीमन ने कहा कि आलोक वर्मा की नियुक्ति 1 फरवरी 2017 को की गई थी। अगर उनका ट्रांसफर करना ही था तो यह अधिकार सिलेक्शन कमिटी को था। नरीमन ने सवाल उठाए कि कैसे सीबीआई निदेशक के अधिकारों को छीना जा सकता है?

बता दे कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का सीवीसी को भेजे गए जवाब लीक होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके अलावा सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार के आरोपों के प्रकाशित होने पर भी कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया था। बता दें कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विशेष जांच टीम के गठन के लिए याचिका डाली है।

सीबीआई बनाम सीबीआई के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की रिपोर्ट पर सुनवाई की थी।आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर करप्शन के आरोप लगने के बाद वर्मा ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था और छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया। उन पर भी करप्शन के आरोप थे, ऐसे में सरकार का कहना था कि स्वतंत्र जांच के लिए दोनों का ही छुट्टी पर जाना जरूरी है।

सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ग्रीन सिग्नल दे चुका है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि फैसलों में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद नागेश्वर राव के लिए गए फैसलों

गुजरात- सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में BJP कार्यकर्ताओं समेत चार गिरफ्तार

(जी.एन.एस.),अहमदाबाद,

गुजरात पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा पर्चा लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो कार्यकर्ताओं और एक उप निरीक्षक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पर्चे की लीक होने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने परीक्षा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले ही रविवार को परीक्षा को रद्द कर दिया।

बता दें कि गुजरात भर में बनाए गए 2,440 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में करीब आठ लाख 75 हजार परीक्षार्थियों को शामिल होना था। मामले में दो आरोपी मनहर पटेल और मुकेश चौधरी सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई ने तत्काल प्रभाव से उनके निलंबन का आदेश दिया है। दो अन्य आरोपी रूपल शर्मा और उप निरीक्षक वी पी पटेल हैं। पटेल गांधीनगर में बेतार (वायरलेस) विभाग में तैनात है। रूपल गांधीनगर में एक हॉस्टल में काम करती हैं और पूर्व पुलिस उप–निरीक्षक की बेटी हैं।

गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक मयूर चावडा ने बताया कि चौधरी और शर्मा को संभावित रूप से

Picture for representational purpose only.

परीक्षा में शामिल होना था। उन्होंने कहा, मुख्य आरोपी यशपाल सोलंकी अब भी फरार है और उसे पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिसागर जिले के लूनावाडा के मूल निवासी सोलंकी ने दिल्ली से यह पर्चा लीक किया था। वह वडोदरा नगर निगम में एक तदर्थ कर्मचारी के तौर पर काम करता है। चावडा ने कहा कि सोलंकी कथित रूप से 30 नवंबर की रात को दिल्ली गया और उसे किसी तरह लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने कहा, 'वह अगले दिन विमान से वापस वडोदरा आ गया और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कुछ लोगों को भेज दिए, जिनमें मनहर पटेल भी शामिल था। उसने इन्हें चौधरी को बढ़ा दिया।' चावडा ने कहा कि उप निरीक्षक वी पी पटेल, मनहर पटेल को जानता था। वह परीक्षा में शामिल हो रहे अपने कुछ अभ्यर्थियों के लिए जवाब चाहता था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

सरकार के भ्रष्ट प्रणाली की फिर पोल खुल गई

लोकरक्षक परीक्षा रद्द करने पर कांग्रेस के सरकार पर प्रहार

सरकारी प्रशासन पूरा बिका है, परीक्षार्थी उम्मीदवारों को दस हजार रुपये का मुआवजा दो : शंकरसिंह वाघेला

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद

लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा अंतिम समय में रद्द होने पर विपक्ष कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने बताया है कि, भाजपा के शासन में सरकारी कार्यक्रमों में पुलिस का चपरासी के जैसे उपयोग होता है। लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा अंतिम समय में रद्द किए जाने से लाखों निर्दोष उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा सरकार के लए यह मामला बहुत ही शर्मजनक कहा जा सकता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा ने बताया है कि, गुजरात की कई महत्वपूर्ण परीक्षा कई बार रद्द होती है। लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द होने से सरकार खुद भी मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। परीक्षार्थी को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार से स्पष्ट मांग है कि आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी पैसे खर्च करके परीक्षा देने गये थे। सभी को खर्च सरकार को देना चाहिए। अधिकारियों में राजशाही देखने को मिल रही है। दूसरे जिलों से विद्यार्थी दो दिन से आये। कई बार इसी तरीके से कई परीक्षा रद्द हो गई है। पहले तलाटी में भी घोटाला सामने आया था। गुजरात में बेरोजगारी का प्रमाण चिंताजनक तरीके से बढ़ गया है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने भी सरकार के भ्रष्ट प्रणाली और लापरवाही के कारण लाखों उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा यह कहकर सरकारी प्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा है कि, यह मामले में फिर एक बार सरकार के भ्रष्ट प्रणाली की पोल खुल गई है। दूसरी तरफ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला ने भी लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द होने के मामले में भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया और लोकरक्षक दल की परीक्षा देने के लिए आये सभी परीक्षार्थी उम्मीदवारों को दस हजार रुपये का मुआवजा देने के लिए सरकार से मांग की गई।

गुजरात : तापमान.........

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
अहमदाबाद समेत कहां-कितना न्यूनतम तापमान रहा वह निम्न प्रकार है।

स्थल	न्यूनतम तापमान
अहमदाबाद	१५
डीसा	१३.४
गांधीनगर	१४.४
वीवी नगर	१७.३
वडोदरा	१५
सूरत	१६.४
वलसाड	१४.१
भावनगर	१६
द्वारका	२०.५
ओखा	२३.३
पोरबंदर	१८.८
राजकोट	१६.२
वेरावल	१९.४
दिव	१५
सुरेन्द्रनगर	१६.२
महुवा	१४
भुज	१७.२
नलिया	१२.८
कंडला पोर्ट	१६.५
कंडला एयरपोर्ट	१२.२

गुजरात में लोकरक्षक भर्ती दल की परीक्षा रद्द किए जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद शहर के एसटी स्टेन्ड पर विद्यार्थी बड़ी संख्या में देखने को मिले। (संपूर्ण समाचार सेवा)

राज्यभर के वकीलों में खुशी की लहर

बार काउंसिल में वेल्फेयर फंड की रिन्युअल फीस में कटौती

जुनियर वकीलों की मांग को लेकर बार काउंसिल के एडमीनिस्ट्रेटीव कमिटी ने रिन्युअल फीस कम की

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

गुजरात राज्य में वकीलों की मौत या निधन के मामले में बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा उनके परिजनों या उत्तराधिकारियों को मौत सहायता की रकम दी जाती है और इसके लिए वेल्फेयर फंड स्कीम के तहत फिलहाल मौत सहायता के तहत वकीलों के परिजनों या उत्तराधिकारियों को तीन लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। जो १.४.२०१९ से मौत सहायता की रकम चार लाख होने जा रही है अब यह वेल्फेयर फंड स्कीम के तहत वकीलों को समय-समय पर अपना सदस्यपद रिन्यु भी कराना होता है, जिसकी रिन्युअल फीस अभी तक २५०० रुपये थी लेकिन वकीलों में विशेष करके जुनियर वकीलों की मांग को ध्यान में लेकर गुजरात बार काउंसिल द्वारा एक महत्व के निर्णय में वेल्फेयर फंड स्कीम की रिन्युअल फीस में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

जिसके अनुसार, वकालत के पांच वर्ष पूरा नहीं किया हो ऐसे जुनियर वकीलों को अब सिर्फ एक हजार रुपये रिन्युअल फीस चुकानी पड़ेगी।

बार काउंसिल के इस निर्णय की वजह से राज्यभर के वकीलों में खुशी की लहर फैल गई यह गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन दिपेन दवे, पूर्व चेयरमैन अनिल सी.केल्ला और एक्जीक्युटीव कमिटी के चेयरमैन करनसिंह बी. वाघेला ने बताया है।

उन्होंने आगे बताया है कि, बार काउंसिल ऑफ गुजरात की रविवार को हुई एडमीनिस्ट्रेटीव कमिटी की बैठक में रिन्युअल फीस में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार जुनियर वकीलों के लिए १००० रुपया किया गया है, इसके अलावा वकालत में एक से १५ वर्ष पूरा किया हो ऐसे वकीलों के लिए वार्षिक १५०० रिन्युअल फीस, १५ से २० वर्ष से प्रेक्टिस करते वकीलों के लिए २००० रुपये और २० वर्ष से ऊपर की प्रेक्टिसवाले वकीलों के लिए २५०० रुपये की रिन्युअल फीस निश्चित की गई है।इस निर्णय की वजह से गुजरातभर के वकीलों को विशेष करके जुनियर वकीलों को काफी राहत मिलेगी।

आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकता तो

हमारी मदद ले सकता है पाकिस्तान : राजनाथ सिंह

(संपूर्ण समाचार सेवा)
जयपुर,

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पेशकश की कि अगर वह अपने दमखम पर आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो भारत की मदद ले सकता है। इसके साथ ही सिंह ने कहा कि देश से नक्सलवाद अगले पांच साल में खत्म हो जाएगा। चुनावी दौर पर पहुंचे सिंह ने कहा, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिका का सहयोग लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई हो सकती है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं हो सकती ? पाकिस्तान को अगर लगता है कि वह अकेले अपने दमखम पर आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकता तो अपने पड़ोसी देश भारत से भी वह सहयोग ले सकता है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित बयान पर सिंह ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी यह संदेश देना चाहता हूं, मुद्दा कश्मीर नहीं है। कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, और रहेगा। मुद्दा है तो आतंकवाद और अगर आतंकवाद पर पाकिस्तान बात करना चाहते हैं तो बात हो सकती है। गृहमंत्री ने कहा, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि आतंकवाद समाप्त हो गया है लेकिन साढ़े चार साल में देश में आतंकवाद की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। यह केवल कश्मीर में सिमट गया है। यहां भी हालात सुधर रहे हैं। हमने पूरे जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक प्रक्रिया में लाकर खड़ा किया है। आतंकवाद का जहां तक सवाल हैं इसमें कोई दो मत नहीं कि यह सबकुछ पाक प्रायोजित है। गृहमंत्री ने कहा कि देश और देश की सीमाएं सुरक्षित है आतंकवाद में कमी आई है और नक्सलवाद कुछ साल में खत्म हो जाएगा।

देश की सीमाएं सुरक्षित है आतंकवाद में कमी आई है नक्सलवाद अगले कुछ साल में खत्म हो जाएगा : गृहमंत्री

गुजरात में अधिकतर क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव

नलिया-कंडला एयरपोर्ट में तापमान १३ डिग्री से भी कम

अहमदाबाद शहर में ठंड बढ़ने के संकेत : तापमान १५ डिग्री : ठंड के बीच लोगों को सावधान रहने की जरुरत

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

अहमदाबाद सहित राज्यभर में अब ठंडी का अनुभव हो रहा है। आज राज्य के बहुत से इलाको में न्यूनतम तापमान शनिवार की तुलना में और अधिक गिरने से ठंडी बढ़ गई है। आज नलिया में न्यूनतम तापमान घटकर १२.८ डिग्री दर्ज हुआ। कंडला एयरपोर्ट में तापमान गिरकर १२.२ डिग्री तक पहुंच गया। अहमदाबाद शहर में तापमान १५ डिग्री रहा। डिसा में १३.४ और गांधीनगर में १४.४ डिग्री तापमान रहा। तापमान में और भी अधिक गिरावट हो सकती है और इससे ठंड का प्रभाव बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। हवामान विभाग के अनुसार आने वाले दो तीन दिनों में लघुत्तम तापमान में कटौती नहीं होगी। नलिया में कल की तुलना में आज उल्लेखनिय कटौती हुई थी।

अभी भी नलिया में तापमान कम होने की संभावना है। अहमदाबाद शहर में सुबह के वक्त लोगों ने अधिक ठंड का अनुभव किया किन्तु दोपहर के समय मिश्र सिजन का अनुभव हुआ। शाम के वक्त भी शहर में लोगों को ठंडी का अनुभव हो रहा है। दुसरी और मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होगा। सौराष्ट्र और कच्छ की बात की जाए तो अधिकांश इलाको में पारा १६ डिग्री से लेकर १८ डिग्री के बीच रहा। ठंडी में एका एक बढौतरी होने से सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग फिटनेस को लेकर और अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। सुबह के वक्त अधिकतर बाग बगीचो में लोगों की भीड़ जुट रही है। मणीनगर इलाके में स्थित लेक फ्रन्ट पर भी बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त जमा हो रहे है। लेक फ्रन्ट में सुबह ६ से ८ बजे तक लोगों को कोई भी फिस के बिना प्रवेश की मंजुरी होने से बड़ी संख्या में लोग यहा पहुंच रहे है। मौसम विभाग ने बताया है कि सौराष्ट्र-कच्छ के अलावा गुजरात के अधिकांश इलाको में अगले दो दिनो के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में परिवर्तन नहीं होगा किन्तु छोटे बच्चे और बड़ी आयु के लोगों को इन दिनो में और अधिक सावधानी से आगे बढ़ने की जरुरत है।

राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह किया

चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष होने चाहिए : अरोड़ा

अरोड़ा ओ पी रावत के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली,

देश के २३वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में रविवार को कार्यभार संभालने वाले सुनील अरोड़ा ने चुनावों को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक बनाने के लिए राजनीतिक दलों और लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया हैं। अरोड़ा, ओ. पी. रावत के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। रावत कल इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के अलावा २०१९ में जम्मू कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव भी उनके ही कार्यकाल के दौरान संपन्न होंगे। उनका कार्यकाल अक्टूबर, २०२१ तक होगा। कार्यभार संभालने के बाद नये मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नैतिक बनाने में सभी हितधारकों-राजनीतिक पार्टियां, मीडिया, नागरिक समाज संगठनों और लोगों से सहयोग करने का अनुरोध किया। अरोड़ा ३१ अगस्त, २०१७ को चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। वह सूचना एवं प्रसारण सचिव और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव रहे थे। राजस्थान कैडर के १९८० बैच के आईएएस अधिकारी अरोड़ा वित्त, कपड़ा जैसे मंत्रालयो और योजना आयोग में भी कार्यरत रहे थे। उन्होंने नागरिक उड्डन मंत्रालय में १९९९-२००२ के बीच संयुक्त सचिव और पांच वर्षों (अतिरिक्त प्रभार के रूप में दो वर्ष और पूर्ण प्रभार के रूप में तीन वर्ष) के लिए भारतीय एयरलाइन्स के सीएमडी के रूप में अपनी सेवाएं दीं। राजस्थान में धौलपुर, अलवर, नागौर और जोधपुर में जिला तैनातियों के अलावा अरोड़ा १९९३-१९९८ के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे थे। वह (२००५-२००८) के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे थे। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क (आईपीआर), उद्योग और निवेश विभागों को भी संभाला था ।

कलोल में पत्नी की मौत के मामले में नया मोड़

वैज्ञानिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की साजिश से विवाद

पुलिस, एफएसएल, संबंधित शासकों को सुप्रीम के फैसले का पालन किए बिना टेस्ट नहीं कराने की नोटिस जारी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

कलोल में पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने और इसकी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। कलोल तहसील पुलिस ने आरोपी पति के पांच दिन का और रिमांड मांगा इसमें एक कारण आरोपी के पोलीग्राफिक और एसटीएस टेस्ट कराने की वजह से इसका रिमान्ड जरूरी होने का बताया गया। थर्ड एडिशनल सीविल न्यायाधीश और ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्टक्लास ए.एम. शुक्ल ने आरोपी का रिमान्ड दे दिया। जिसकी वजह से रिमान्ड के दायरे में पुलिस आरोपी पति के वैज्ञानिक टेस्ट बाहर ही बाहर एफएसएल में नहीं करा दे इसके लिए वरिष्ठ वकील आरजे. गोस्वामी द्वारा कलोल तहसील पुलिस, एफएसएल के डायरेक्टर, गृहविभाग सहित के सरकार के संबंधित शासकों को महत्व की कानूनी नोटिस भेजकर स्पष्ट सूचना दी गई है।

प्रस्तुत केस में सुप्रीम कोर्ट के शेल्वी विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक के २०१० (७) एससीसी पेज नंबर-२६३ फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी परिस्थिति में आरोपी पति के वैज्ञानिक टेस्ट नहीं करना। अन्यथा यह सभी शासकों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भंग और अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी।

कलोल के पंचवटी क्षेत्र में संस्कृति बंगले में रहते संदीप प्रवीणभाई पटेल (मूल वतन, बोरीसना) की शादी २००२ में शीतलबहन के साथ हुई थी। शादी में उनको दो संतान थे। संदीपभाई नागरिकों को विदेश भेजने के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें पिछले कई दिनों में कर्जा हो जाने से अपनी पत्नी को माइके से पैसे की मदद लाने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं ला सकने से अक्सर शारीरिक मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और इस मामले में आखिर में गत महीने में नर्मदा नहर में कूदकर पत्नी शीतलबहन ने आत्महत्या कर ली यह शिकायत में आरोप लगाया गया है। यह अपराध में पहले कलोल के एडिशनल सीनियर सीविल न्यायाधीश और ज्युडीशियल मेजिस्ट्रेट डी.एस. ठाकर ने आरोपी पति के सात दिन का रिमांड मंजूर किया गया।

आईआईएम-ए के द्वारा अध्ययन किया गया

निजीअस्पतालों में सी-सेक्शन से प्रसव की संख्या अधिक हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,

भारत में एक साल में निजी अस्पतालों में हुए ७० लाख प्रसवों में से नौ लाख प्रसव बगैर पूर्व योजना के सीजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) के जरिए हुए जिन्हें रोका जा सकता था और ये ऑपरेशन मुख्यत: पैसा कमाने के लिए किए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) ने एक अध्ययन में यह कहा है। शिशुओं के चिकित्सीय रूप से अनुचित ऐसे जन्म से ना केवल लोगों की जेब पर बोझ पडता हैं बल्कि इससे स्तनपान कराने में देरी हुई, शिशु का वजन कम हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके अलावा नवजातों को अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा।

आईआईएम-ए के फैकल्टी सदस्य अंबरीश डोंगरे और छात्र मितुल सुराना ने यह अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं प्रसव के लिए निजी अस्पतालों का चयन करती है उनमें सरकारी अस्पतालों के मुकाबले बगैर पूर्व योजना के सी-सेक्शन से बच्चे को जन्म देने की आशंका १३.५ से १४ फीसदी अधिक होती है।

ये आंकड़ें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के २०१५-१६ में हुए चौथे चरण पर आधारित है जिसमें पाया गया कि भारत में निजी अस्पतालों में ४०.९ फीसदी प्रसव सी-सेक्शन के जरिए हुए जबकि सरकारी अस्पतालों में यह दर ११.९ प्रतिशत रही। अध्ययन में कहा गया है कि सी-सेक्शन के जरिए नवजातों का जन्म कराने के पीछे मुख्य वजह वित्तीय लाभ कमाना रहा। एनएफएचएस का हवाला देते हुए आईआईएम-ए के अध्ययन में कहा गया है कि किसी निजी अस्पताल में प्राकृतिक तरीके से प्रसव पर औसत खर्च १०,८१४ रुपये होता है जबकि सी-सेक्शन से २३,९७८ रुपये होता है।

अध्ययन में कहा गाय है, चिकित्सीय तौर पर स्पष्ट किया जाए तो सी-सेक्शन से प्रसव से मातृ और शिशु मृत्यु दर और बीमारी से बचाव होता है लेकिन जब जरुरत ना हो तब सी-सेक्शन से प्रसव कराया जाए तो इससे मां और बच्चे दोनों पर काफी बोझ पड़ता है जो जेब पर पड़ने वाले बोझ से भी अधिक होता है।

इसमें कहा गया है कि सी-सेक्शन से प्रसव की संख्या कम करने के लिए सरकार को ना केवल उपकरणों और कर्मचारियों के लिहाज से बल्कि अस्पताल के समय, सेवा प्रदाताओं की अनुपस्थिति और वर्ताव के लिहाज से भी सरकारी अस्पतालों को मजबुत करना होगा।

नौ लाख प्रसव सीजेरियन सेक्शन के जरिए हुए जिन्हें रोका जा सकता था, ये पैसा कमाने के लिए किए गए

आरबीआई की बैठक ३ दिसंबर से शुरू होगी

आर्थिक आंकड़े इस हफ्ते तय करेंगे बाजार की चाल

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ५वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दर पर अपना फैसला लेगा

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली,

भारयी रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक, वृहद आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुख और रुपये की चाल से इस सप्ताह बाजार की दिशा तय होगी। विशेषज्ञों ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि इस सप्ताह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई आंकड़े भी आने हैं, जो बाजार धारणा को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का भी बाजार पर असर दिखाई देगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दो साल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद देश की आर्थिक वृद्धि दर सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में धीमी पड़कर ७.१ प्रतिशत रह गई।

पहली तिमाही के मुकाबले खपत मांग में कमी और कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में नरमी के रुझान से वृद्धि दर में कमी रही। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ५वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दर पर फैसला लेगा।

इसका भी बाजार पर असर होगा। यह बैठक ३ दिसंबर से शुरू होकर ५ दिसंबर को समाप्त होगी। विशेषज्ञों ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में नरमी और मुद्रास्फीति में कमी के बाद आरबीआई नीतिगत दर पर यथास्थिति कायम रख सकता है अर्थात् वह दर में वृद्धि नहीं करेगा।

जियोजित फाईनैंशल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, निवेशकों की नजर जी-२० शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के बीच होने की बैठक के नतीजों और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की आगामी बैठक पर होगी। ओपेक की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के संकेत मिल रहे हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from 131, Dharmanagar Society, Highway Road, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH